संख्या : 9 54 / XLI-1 / 2016-87 / 2014

प्रेषक,

डी0 सेन्थिल पाण्डियन, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, श्रीनगर (पौड़ी गढवाल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग-1

देहरादून। दिनांक : 10 अगस्त, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जाति उपयोजना (एस०सी०एस०पी०) एवं जनजाति उपयोजना (टी०एस०पी०) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में। महोदय.

कृपया वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—490 / xxvIII-1 / 2016 दिनांक 31.03.2016, शासनादेश संख्या—487 / xxvIII-1 / 2016 दिनांक 26.07.2016 एवं आपके पत्र संख्या—303 / नि0प्रा0शि0 / लेख बजट / 2016—17 दिनांक 17.06.2016 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016—17 के लेखानुदान में विषयगत योजनान्तर्गत अनुदान संख्या—30 एवं 31 में पूंजीगत एवं राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि क्रमशः ₹ 16.67 लाख, 26.34 लाख (16.67 + 9.67) कुल ₹ 43.01 लाख (₹ तैंतालिस लाख एक हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : —

- उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31.03.2016 में वित्त विभाग द्वारा दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 2. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
- 3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिये किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।
- 4. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्था द्वारा धनराशि को किसी भी दशा में आहरित कर बैंक खाते में न रखा जाए। यदि संस्था द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान धनराशि बैंक खाते में रख कर ब्याज अर्जित किया गया हो तो अर्जित ब्याज की धनराशि को कम करते हुए शेष धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव ही शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 5. उपकरणों / निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस संबंध में समय—समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।
- 6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय—समय पर जारी कियो गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

•

- 7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का ववरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
- 8. मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016—17 के लेखानुदान में 'अनुदान संख्या—30' के 'पूंजीगत पक्ष' के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगतत परिव्यय—02—तकनीकी शिक्षा—104—बहुशिल्प'' के संबंधित मानक मद एवं अनुदान संख्या—31 के 'राजस्व पक्ष' के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2203—तकनीकी शिक्षा—00—105—बहुशिल्प—03—सामान्य पॉलीटैक्निक'' के मानक मद—12—कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण धनराशि 26—मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र में 42—अन्य व्यय में 46—कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।
- 3— यह आदेश शासनादेश संख्या—183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. (संलग्नक—1) के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 31.03. 2016 एवं दिनांक 26.07.2016 के द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय, (डीo सेन्थिल पाण्डियन) सचिव।

संख्या : 954 (1)/xLI(1)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
- 2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
- 3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, उत्तराखण्ड।
- 6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
- 8. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9 निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10. गार्ड फाईल।

अस्त्रा सं, (सुनील सिंह) उप सचिव।

per Jul D